ISSN (ELECTRONIC): 2945-3135

डा० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (2026). *भारत-जापान सम्बन्धों के मध्य वैश्विक व सामाजिक साझेदारी का एक अध्ययन.* International Journal of Multidisciplinary Research & Review, 5(1), 68-72.

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & REVIEWS

journal homepage: www.ijmrr.online/index.php/home

भारत-जापान सम्बन्धों के मध्य वैश्विक व सामाजिक साझेदारी का एक अध्ययन

डा० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल

असिस्टेंट प्रोफेसर - सैन्य विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नई टिहरी,टिहरी गढ़वाल - 249001, उत्तराखण्ड,भारत.

How to Cite the Article: डा० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (2026). *भारत-जापान सम्बन्धों के मध्य वैश्विक व सामाजिक साझेदारी का एक अध्ययन.* International Journal of Multidisciplinary Research & Review, 5(1), 68-72.

https://doi.org/10.56815/ijmrr.v5i1.2026.68-72

भारत और जापान के बीच की मित्रता सदियों पुरानी है, जिसकी नींव बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ रखी गई थी दोनो देश अपनी वैश्विक व सामरिक साझेरारी को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहे है। आधुनिक युग में. यह सम्बन्ध केवल सांस्कृतिक आदान–प्रदान तक सीमित नहीं है वल्कि यह एक विशेप वैश्विक रणनीति और वैश्विक साझेदारी में बदल गये हैं। भारत– जापान के मध्य आपसी सम्बन्ध अत्यन्त मैत्रीपूर्ण रहे है। इन सम्बन्धों की जड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रही है। जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के वीच सम्बन्धों में निरन्तर विकास होता रहा है, जो सतत विकास के माध्यम से शान्ति, स्थिरता और आपसी समृद्धि पर केंद्रित है। उनकी साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों, बहुलबाद, खुले समाज और कानून के शासन पर आधारित है, यह राजनीतिक, आर्थिक, और रणनीतिक हितो के गहरे संरक्षण को दर्शाता है। दोनो देश वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने में एक दूसरे को सक्षम भागीदार के रूप में देखते हैं।

उल्लेखनीय है कि राजनतिक सम्बन्धों के पहले दशक में, भारत और जापान ने महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आदान–प्रदान किये जिसमे 1957 में जापानी प्रधानमंत्री नोबुसुके किपी की भारत यात्रा और उसी वर्प प्रधान मंत्री नेहरू की टोक्यो यात्रा शामिल थी। यद्यपि, बाद के दशकों में यात्रा का दौर धीमा हो गया और 1980 के दशक तक कम उच्च स्तरीय यात्राऐं हुई। हांलाकि 1980 के दशक मे जापन के सहयोग से भारत में मारुति – सुजुकी कार कम्पनी की स्थापना की गई। साथ ही भारत की सबसे अधिक सरकारी विकास सहायता (Official development Assistance(ODA) जापान से ही

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

डा० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (2026). *भारत-जापान सम्बन्धों के मध्य वैश्विक व सामाजिक साझेदारी का एक अध्ययन.* International Journal of Multidisciplinary Research & Review, 5(1), 68-72.

प्राप्त हुई है। इसके अलावा भारत में ढांचागत सुविधाओं के विकास जैसे दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना तथा बुलेट ट्रेन के विकास मे भी जापान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत व जापान के बीच सन् 1952 में कूटनीतिक सम्बन्धों की स्थापना के बाद से ही सम्बन्धों का विस्तार होता रहा है. वर्तमान में जापान, चीन व भारत के बाद एशिया की तीसरी तथा विश्व की पाँचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. जापान भारत के लिए आर्थिक सहायता तथा आधुनिक तकनीकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है. यद्यपि शीत युद्ध काल में जापान सामरिक रूप से अमेरिका व यूरोपीय देशों के गुट के करीब रहा है, लेकिन भारत के साथ जापान की आर्थिक व विकास साझेदारी में कोई कमी नहीं आई उत्तर–शीत युद्ध काल में भारत द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों के बाद तथा चीन की आक्रामक नीतियों के कारण दोनों देशों के बीच आर्थिक व सामरिक सहयोग के नए अवसर प्राप्त हुए. दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी सहयोग समझौते को भी लागू कर दिया है. चीन की सामरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए दोनों देशों के बीच एक साझा सामरिक दृष्टिकोण विकसित हुआ है इसके अन्तर्गत दोनों देश हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में एक खुली, स्वतंत्र तथा नियम–आधारित व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर हैं, इसके लिए दोनों देशों ने अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड नामक सामरिक सहयोग मंच की स्थापना की है. वास्तव में हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र में इस तरह के सामरिक मंच की स्थापना का विचार सबसे पहले 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने दिया था।

स्मरणीय है कि द्वितीय विश्व युद्ध से हुए नुकसान के बावजूद जापान ने तेजी से अपना आर्थिक विकास किया है. वर्ष 2010 तक चीन के उदय से पूर्व जापान लम्बे समय तक अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा है. इसके बाद जर्मनी व भारत के आगे आने के बाद इस समय जापान विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी तथा एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. भारत द्वारा जापान के साथ अपने सम्बन्धों को कितना महत्व दिया जाता है इसका पता इस बात से ही चलता है कि रूस तथा चीन के बाद जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने प्रति वर्ष शिखर सम्मेलनों के आयोजन की व्यवस्था की है. दोनों देशों के बीच पहला शिखर सम्मेलन 2006 में आयोजित किया गया था, तब से लेकर अब तक दोनों देश निरन्तर इन शिखर सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं. ये शिखर सम्मेलन बारी–बारी से दोनों देशों में आयोजित किए जाते हैं. ये शिखर सम्मेलन दोनों देशों के बीच उच्च–स्तरीय कूटनीतिक व सामरिक विचार–विमर्श का महत्वपूर्ण साधन हैं।

भारत–जापान शिखर सम्मेलन

भारत–जापान का 15वाँ शिखर सम्मेलन 29 व 30 अगस्त, 2025 को जापान की राजधानी टोकियो में सम्पन्न हुआ. इस अवसर पर भारत के प्रधानमत्री मोदी तथा जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इशिबा शिगेरू के बीच प्रतिनिधिमण्डल स्तर पर विभिन्न द्विपक्षीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार–विमर्श किया गया दोनों देशों ने वैश्विक परिस्थितियों के आलोक में एक स्वतत्र, शान्तिपूर्ण व खुले हिन्द–प्रशान्त की स्थापना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया दोनों देशों ने पूर्वी चाइना द्वारा समुद में तनाव की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में सेनकाक् द्वीप समूह पर अधिकार को लेकर चीन व जापान में विवाद चल रहा है. दोनों नेताओं ने गाजा की स्थिति तथा म्यांमार के सिविल युद्ध पर भी चिन्ता व्यक्त की तथा इसके शान्तिपूर्ण समाधान पर बल दिया की दोनों देशों ने भारत में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले तथा उत्तरी कोरिया द्वारा लम्बी दूरी की मिसाइलों के प्रदर्शन को अस्वीकार्य बताया दोनों नेताओं ने अफ्रीका में भारत व जापान की सयुक्त विकास साझेदारी को शुरू करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे वह चीन के बढ़ते सामरिक प्रभाव को रोकने में मदद मिलेगी इसके साथ ही दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया इन सुधारों में इसकी आम सदस्य संख्या तथा स्थायी सदस्यों की संख्या में विस्तार किया जाना शामिल है. उल्लेखनीय है

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

डा० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (2026). *भारत-जापान सम्बन्धों के मध्य वैश्विक व सामाजिक साझेदारी का एक अध्ययन.* International Journal of Multidisciplinary Research & Review, 5(1), 68-72.

कि भारत व जापान दोनों देश ब्राजील व जर्मनी के साथ जी–4 समूह के सदस्य है. जो सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता हेतु दावा कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों राष्ट्रों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया इस संयुक्त वक्तव्य के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. वर्तमान में भारत व जापान विशिष्ट सामरिक व वैश्विक साझेदारी (Special Strategic and Global Partnership) को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं यह साझेदारी सांस्कृतिक सम्बन्धों, साझा हितों, आपसी विश्वास तथा साझा सामरिक दृष्टिकोण पर आधारित है।
2. दोनों देशों ने साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए प्राथमिकता वाले तीन क्षेत्रों को चिन्हित किया है–प्रतिरक्षा व सुरक्षा सहयोग, आर्थिक साझेदारी तथा दोनों देशों की जनता के बीच आदान–प्रदान
3. दोनों देशों ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को स्वीकार किया–

- अगले दशक यानि 2035 तक के लिए दोनों राष्ट्रों द्वारा 8 क्षेत्रों का रोडमैप प्रस्तुत किया गया है. जिसमें आर्थिक सहयोग, आर्थिक सुरक्षा, जन संसाधनों की गति–शीलता, पर्यावरण, तकनीकी, स्वास्थ्य, जनता के बीच सम्बन्ध तथा भारतीय राज्यों व जापान के प्रान्तों (Perfactures) परफेक्चरस के बीच सहयोग को बढावा दिया जाएगा।
- वर्तमान भू–राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को उच्चीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।
- भारत–जापान मानव संसाधन आदान–प्रदान तथा सहयोग के लिए अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच 5 लाख व्यक्तियों का आदान–प्रदान किया जाएगा।

4. दोनों राष्ट्रों ने भारत–जापान आर्थिक सुरक्षा पहल (India-Japan Economic Security Intiative) नामक एक नई पहल शुरू की है. इसमें दोनों देश आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आपसी सहयोग को आगे बढ़ाएंगे।
5. ए.आई. तकनीकी के विकास के लिए दोनो राष्ट्रों द्वारा ए.आई. सहयोग पहल (JAPAN INDIA AI COPERATION INTIATIVE) के आरम्भ करने के लिए द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी।
6. दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग को बढाने के लिए द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश के विस्तार पर बल दिया. वर्ष 2022 में जापान ने भारत में 5 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा था जिसे बढाकर 10 ट्रिलियन येन (करीब 67–68 बिलियन) निवेश करने का निर्णय लिया गया दोनों राष्ट्रों द्वारा व्यापार के विस्तार तथा विविधीकरण करने का भी निर्णय लिया गया है।
7. वर्तमान में जापान के सहयोग से भारत के उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में सम्पर्कता विकास की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है. इसके लिए दोनों राष्ट्रों द्वारा एक्ट ईस्ट फोरम की भी स्थापना की गई है. दोनों नेताओं ने जापान के सहयोग से बन रही मुम्बई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के शीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की।
8. जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत–जापान क्लीन इनर्जी साझेदारी को और अधिक मजबूत करने तथा क्लीन इनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया इसके लिए दोनों देशों ने इस अवसर पर ग्रीन हाइड्रोजन तथा कार्बन क्रेडिट मार्केट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति–पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए।
9. संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों के बीच विज्ञान व तकनीकी में सहयोग बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में शैक्षणिक सस्थाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करने व वैज्ञानिकों के आदान–प्रदान पर जोर विया गया।
10. शिखर सम्मेलन के दौरान आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए मानव संसाधनों के आदान–प्रदान पर विशेष जोर दिया गया।

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

डा० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (2026). *भारत-जापान सम्बन्धों के मध्य वैश्विक व सामाजिक साझेदारी का एक अध्ययन.* International Journal of Multidisciplinary Research & Review, 5(1), 68-72.

स्मरणीय है कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते निम्नलिखित हैं–अगले दशक के लिए भारत–जापान संयुक्त विजन दस्तावेज, सुरक्षा मामलों मे सहयोग हेतु संयुक्त घोषणापत्र, अगले 5 वर्षों के लिए मानव संसाधनों के आदान–प्रदान पर समझौता, संयुक्त क्रेडिट को लागू करने का समझौता, डिजिटल साझेदारी–2 समझौता, खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को समझौता, संयुक्त अन्तरिक्ष कार्यक्रम लूपेक्स (LUPEX-Lunar Polar Experiment) के क्रियान्वयन पर समझौता, स्वच्छ अमोनिया हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता, सांस्कृतिक आदान–प्रदान का समझौता, घरेलू दूषित जल के शोधन में सहयोग का समझौता, पर्यावरण में सहयोग का समझौता, विदेशी मामलों में प्रशिक्षण हेतु सुषमा स्वराज संस्थान की स्थापना पर समझौता तथा खेलकूद व विज्ञान तथा तकनीकी में सहयोग का समझौता प्रमुख है।

उल्लेखनीय है कि शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों राष्ट्रों द्वारा अपनी आर्थिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आपसी बातचीत व सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे. यहाँ आर्थिक सुरक्षा से तात्पर्य आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति बनाए रखने से है. एक तरफ चीन आवश्यक धातुओं के आपूर्ति पर रोक लगाकर आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने कई देशों के विरुद्ध एकपक्षीय व्यापार शुल्क लगाने की घोषणा की है. इससे दोनों देशों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव होगा. अतः आर्थिक सुरक्षा के लिए दोनों देशों में सहयोग आवश्यक है। दोनों देशों ने अपने द्विपक्षय सम्बन्धों को नई मजबूती व नई दिशा देने के लिए वर्ष 2000 में वैश्विक साझेदारी की स्थापना की. इसके बाद इस साझेदारी को उच्चीकृत 2006 में वैश्विक व सामरिक साझेदारी की शुरुआत की इसमें पुनः विस्तार करते हुए 2014 में दोनों देशों ने विशेष वैश्विक व सामरिक साझेदारी की स्थापना का निर्णय लिया. वर्तमान में दोनों देश इसी साझेदारी को व्यापक बनाने तथा मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सुरक्षा, आर्थिक सहयोग तथा जनता के आदान–प्रदान को प्राथमिकता प्रदान की है. इसके साथ ही नई परिस्थितियों के आलोक में आर्थिक सुरक्षा सहयोग की नई पहल की है. दोनों देश वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भी सहयोग कर रहे हैं. निवेश तथा व्यापार के अलावा दोनों के बीच विकास साझेदारी, नई तकनीकी जैसे एआई तकनीकी, स्वच्छ इनर्जी में सहयोग तथा क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग को आगे बढ़ाना 15वें शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ है. चूँकि दोनों देशों के आर्थिक विकास की स्थिति एक–दूसरे की पूरक है तथा दोनों के बीच विवाद का कोई बिन्दु नहीं है, अतः भविष्य में भी दोनों देशों की बहुआयामी साझेदारी के विस्तार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं।

1. AUTHOR(S) CONTRIBUTION

The writers affirm that they have no connections to, or engagement with, any group or body that provides financial or non-financial assistance for the topics or resources covered in this manuscript.

2. CONFLICTS OF INTEREST

The authors declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

3. PLAGIARISM POLICY

All authors declare that any kind of violation of plagiarism, copyright and ethical matters will take care by all authors. Journal and editors are not liable for aforesaid matters.

4. SOURCES OF FUNDING

The authors received no financial aid to support for the research.

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License

डा० दीपेन्द्र सिंह तोपवाल (2026). *भारत-जापान सम्बन्धों के मध्य वैश्विक व सामाजिक साझेदारी का एक अध्ययन.* International Journal of Multidisciplinary Research & Review, 5(1), 68-72.

सन्दर्भ सूची।–

1. डी0 के0 हरि, हेमा हरि (2017) इण्डो–जापान सम्बन्ध, श्री श्री पब्लिकेशन पृ0 3
2. वर्ल्ड फोकस 2020
3. प्रतियोगिता दर्पण – नवम्बर 2025
4. www.Jcwa.com
5. vidyawarta, oct to dec 2016, Issue 16, Vol-09
6. वर्ल्ड फोकस 2018
7. International Journal of creative Research Thoughts (IJCRT)Volume 12, Issue 11, November 2024
8. दैनिक जागरण
9. राष्ट्रीय सहारा
10. हिन्दुस्तान टाइम्स
11. https://www-mofa-go-jp/region/asia-Paci/india/data-htm/
12. https:// www.isert.org

The work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License